Year-9-10; 2018-19
ISSN–2231-1130

Impact Factor – 3.521(IIJIF)
●●●●VEETHIKA●●●

प्राथमिक शिक्षा की समस्याएँ–उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के विशेष सन्दर्भ में

डॉ ० अनिल कुमार पाण्डेय*

जगत के अन्य जीवों से मानव की श्रेष्ठता का रहस्य विवेकपूर्ण ढंग से सीखने में संनिहित है। यही कारण हैं कि प्रारम्भ से ही मानव सीखने की कला को सुव्यवस्थित करने का प्रयास करता रहा है। साथ ही सीखने और सिखाने को प्रारम्भिक समाज निर्माण के साथ ही श्रेष्ठ व सम्मानजनक स्थान दिया जाने लगा । वर्तमान विश्व में लगभग सभी राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रारम्भिक स्तर की औपचारिक शिक्षा देने के लिए कम से कम पर दृढ संकल्पित हो गये है। विभेदकारी आयामों पर बिना ध्यान दिए जन सामान्य को प्रारम्भिक शिक्षा मुहैया कराना सभी सरकारों की आवश्यकता एवं दायित्व हो गया है और जहां भी संसाधनों के अभाव के कारण इस पुनीत लक्ष्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है वहां पर विश्व के सभी मानवतावादी चिन्तक व्यक्ति एवं राष्ट्र तुरन्त ही सहयोग प्रदान करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। यूनिसेफ जैसा सशक्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसका प्रमाण है।

भारत जैसा सांस्कृतिक राष्ट्र अपने उद्भव से ही ज्ञान केन्द्रित समाज के निर्माण के लिए दृढ़ संकल्पित रहा है। ज्ञानार्जन, चिन्तन, मनन एवं उसके विस्तार के लिए समाज का एक विशेष वर्ग ही इसे अपना दायित्व स्वीकार कर लिया था। प्राचीन समृद्ध वांगमय इसके प्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। विश्व उस काल में जहां समाजीकरण के प्रारम्भिक दशा में था वहीं पर भारत समृद्धतम् साहित्य (वेदों एवं पुराणों) की रचना कर चुका था। अनेकानेक परिस्थितिजन्य विषमताओं के बावजूद प्रत्येक आक्रमणकारी आक्रांताओं ने यह स्वीकार किया कि भारत में ज्ञानार्जन के केन्द्रों (विद्यालयों) की जड़े इतनी गहरी है कि इन्हें बदले बिना शक्ति के प्रयोग एवं आघातों से भारत को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इस श्रेष्ठ परम्परा को स्वतंत्रता के पश्चात भी राष्ट्रीय नेतृत्व अक्षुण्ण बनाये रखा और सदैव विभिन्न रीतियों एवं नीतियों से प्रयास करता रहा है कि मानव को संसाधनों को विकसित करने के लिए श्रेष्ठता प्रदान करने का प्रयासरत् रहा है । इस कड़ी में संविधान निर्माण में ही अनुच्छेद –45 के द्वारा शिक्षित करने का प्रावधान कर दिया गया। संवैधानिक प्रावधान एवं समय–समय पर किए गये अनेकानेक प्रयासों के बावजूद भी हम आज तक सबको शिक्षित करने के प्रथम चरण, साक्षर' बनाने का संकल्प जिसे दस वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य था उसे अब तक पूरा नहीं कर सके। संवैधानिक प्रावधान, राजकीय प्रयास, जनसहभागिता, भारी भरकम राजकीय निवेश के बाद भी प्रस्तुत लक्ष्य की सम्प्राप्ति इस स्वतंत्रयोत्तर दीर्घावधि में अब तक पूरा नहीं हो सका । जो उपलब्धियां है वे भी उसमें क्रमशः सम्पन्न होते गए वर्ग की शिक्षा के प्रति सकारात्मक आस्था और निजी विद्यालयों की उपलब्धता महत्वपूर्ण प्रभावी कारक रहे। वर्तमान में एक ओर नगरीय व अपेक्षया सम्पन्न वर्ग में अशिक्षा की स्थिति न्यूनतम स्तर पर पहुंच गयी है य वहीं दूसरी ओर ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्र में जहां विकास का प्रकाश न्यूनतम स्तर पर पहुंच पाया है वहां पर शैक्षिक रोशनी का भी अभाव दृष्टिगत होता है। गरीबी एवं भुगतान की अपर्याप्त क्षमता के कारण शिक्षा का उजियारा पहुंचाने का मुख्य साधन सरकार द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालय ही रह गए हैं। निम्नलिखित आकड़ों पर ध्यान दिया जाय तो विद्यार्थियों की दशा स्वतः स्पष्ट हो जाती है प्रस्तुत न्यादर्श से वर्तमान स्थिति का पता चलता है बावजूद इसके अबतक सबको शिक्षित करने का न्यूनतम लक्ष्य अभी भी दूर की कौड़ी बना हुआ है। अंग्रारित सारणी द्वारा विद्यार्थियों के अवबोध के स्तर का प्रतिशतवार विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है

कक्षा	भाषा (लिखना–पढ़ना)		गणित	विज्ञान
	हिन्दी	अंग्रेजी	जोड़, घटाना, गुणा की जानकारी	प्रारम्भिक ज्ञान
तीन	25	06	17	14
पाँच	53	22	32	37
आठ	68	33	43	46

प्रस्तुत आंकड़े लखनऊ जनपद के मोहनलालगंज, माल एवं बक्शी के तालाब उपखण्ड के इक्कीस (21) विद्यालयों में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर है। उक्त सारणी के अवलोकन से प्राथमिक शिक्षा की यथास्थिति का आभास हो जा रहा है ।

*एसो० प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विभाग, बी०एस०एन०वी० पी०जी० कालेज, लखनऊ(उ० प्र०)

	Revenue Expenditure on Govt. Primary and Upper Primary School.	Revenue Expenditure on Govt. Primary and & upper secondary School.	Revenue Expenditure on pension of Govt. Elementary Teachers	Total Revenue Expenditure On Govt. Elementary Teachers	No. of students in class 01-08 in Govt. Elementary and Secondary School	Annual per pupil expenditure	Monthly per pupil expenditure	Revised calculation of per pupil expenditure in UP Govt. elementary school after correcting enrolment No.		
								No. of student in class 01-08 in Govt. Elementary and Secondary School	Annual per pupil expenditure	Monthly per pupil expenditure
2013-14	18622	597	3382	22601	17712153	12760	1063	14523965	15561	1297
2014-15	24272	514	4020	28806	16844258	17101	1425	13812292	20855	1738
2015-16	31758	604	4500	36862	16018889	23012	1918	13135489	28063	2340

- Govt. per pupil expenditure in Uttar Pradesh Implication for reimbursement of Private school under RTE Act. (November 2015)
- Professor GeetaKingdon , UCL Institute of Education University College London
- Professor Mohd. Muzammil , VC Agra University

उक्त सारणी से यह भी स्पष्ट हो जा रहा है कि शिक्षा प्राप्ति का लक्ष्य' मात्र भारी निवेश' से ही पूरा नहीं किया जा सकता है। इसके लिए शिक्षक एवं समाज एवं प्रशासन सभी को सही सन्दर्भो में ठीक से प्रयास करना होगा। शिक्षकों की गुणवत्ता, दायित्व बोध, शिक्षण अभिरूचि, ज्ञान, सम्प्रेषणीयता, निरपेक्ष चिन्नतन, मानवीय एवं राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्था, नैतिकता जैसे मौलिक गुणों को भी ध्यान में रखकर नियुक्ति किया जाय। समय–समय पर इनका उक्त सन्दर्भो में धरातलीय मूल्यांकन अत्यन्त आवश्यक ही नहीं अपितु अपरिहार्य हो गया है। उ0प्र0 सरकार द्वारा परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए तात्कालिक सरकार द्वारा अस्थायी शिक्षकों की व्यवस्था के रूप में ''शिक्षा मित्रों'' का चयन किया गया। इस नियुक्ति में शिक्षक पात्रता को पूर्णतः नजरन्दाज किया गया जो वर्तमान में ऐन–केन प्रकारेण या तो पूर्णकालिक शिक्षक बन गए हैं या बनने की प्रक्रिया में है। ऐसे शिक्षिकों में गुणवत्ता के अभाव के फलस्वरूप इन्हें "शिक्षा मित्र' नहीं अपितु' शिक्षा–शत्रु' ही कहा जाना उचित होगा। ऐसे शिक्षक अपने जीवन काल में औसतन दो हजार विद्यार्थियों को या तो शिक्षा से वंचित कर देते हैं या उनमें शिक्षा के प्रति विकर्षण उत्पन्न कर दे रहे हैं। भारत की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था (उच्चतम् –न्यायालय) भी इनके शिक्षक होने की पात्रता एवं इनके दुष्गामी प्रभावों की ओर कई बार इंगित कर चुकी है ।

अयोग्यता, पलायनवादिता, अकर्मण्यता, दायित्वहीनता जैसे कारक कुचक्र, ईर्ष्या एवं द्वेष की जननी होती है। फलतः ऐसा व्यक्ति न ही कार्यों के

निर्वहन में रुचि लेता है और न ही राष्ट्रीय विकास में सहयोग दे पाता है जिससे प्रारम्भ में व्यक्ति का और अन्ततः समाज व राष्ट्र की अपूर्णीय क्षति होती है। साथ ही एक नकारात्मक कार्य – संस्कृति का भी विकास हो जाता है जो क्रमशः राष्ट्र से जनकल्याण का आधार बनाकर संख्या बल के आधार पर अनैतिक मांग करने लगते हैं, (विशेषरूप से प्रजातांत्रिक राष्ट्रों में)।

स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क सम्भव है इस अवधारणा को मार्गदर्शक सिद्धान्त स्वीकार कर मध्याहन भोजन जैसी खर्चीली योजना भारत सरकार द्वारा अपनायी गयी। इस प्रलोभनकारी योजना का प्रभाव भी नकारात्मक ही रहा, यह भी एक स्थापित सत्य है। विद्यार्थी एवं शिक्षक दोनो खाने–खिलाने को ही नौकरी और दायित्व समझ लिए हैं फलतः शिक्षण एक गौण कार्य हो गया है। ऐसी दशा में यह अमनोवैज्ञानिक प्रलोभनकारी विनिवेश न तो शिक्षा के लक्ष्य को पूरा कर पा रहा है और न ही पोषण के।

अभिभावकों का शिक्षा के प्रति सही सन्दर्भो में जागरूक न होना, शिक्षा के धरातलीय महत्त्व को न जानना, गरीबी, बेराजगारी, कई बच्चों का होना जैसे अनेक वैयक्तिक कारणों के अतिरिक्त सामाजिक सम्मान, सरकार के प्रति अनास्तिक होना, शिक्षा से रोजगार न प्राप्त करने की भग्नाशा (विशेषकर इस्लाम के अनुयायियों में) जैसे अनेकानेक समस्याएं है जिन पर गहन, चिन्तन, मनन एवं अवलोकन की आवश्यकता है एवं तदजन्य परिणामों के सापेक्ष नीतियों में परिवर्तन एवं परिमार्जन उपयुक्त होगा। दृढ राजनैतिक इच्छा शक्ति से किए गए उपरोक्त सन्दर्भो के आलोक में प्रयास कदाचित हमें प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं से निजात दिला पाएगें।